

भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति

मयंक कुषवाहा

समाजशास्त्र विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय

सांप्रदायिकता का अर्थ है, सामाजिक धार्मिक समूहों की वह प्रवृत्ति जिसके द्वारा वे दूसरे समूहों के हितों को नुकसान पहुँचाकर अपने लिए और अधिक सामाजिक एवं राजनितिक ताकत को प्राप्त करने के प्रयत्न करते हैं। यह एक विचारधारा है, जिसके तहत समाज धार्मिक समुदायों में विभक्त होता है। जिनके हित भिन्न-भिन्न होते हैं और कभी-कभी एक दूसरे से विल्कुल विरुद्ध होते हैं। दूसरे शब्दों में सांप्रदायिकता को विषिष्ट समुदायों के स्वार्थी हितों द्वारा राजनीतिक कार्यों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यह राजनीतिक रूप से एक ऐसी विकृत नीति है, जो राष्ट्रवाद अथवा राष्ट्रीयता की भावना का विरोध करती है। वस्तुतः यह बहुजातीय, बहुधार्मिक तथा बहुभाषायी समुदायों के सहअस्तित्व के समक्ष उपस्थित एक चुनौती हैं, जिसकी सबसे गंभीर अभिव्यक्ति संगठित सांप्रदायिक दंगों और हिंसा में होती है। यह एक ऐसे षत्रुभाव को विकसित करती है, जिससे सांप्रदायिक व्यक्ति या संगठन विशेष समुदाय पर गलत दोशारोपण, क्षति पहुँचाने और नियोजित तरीके से अपमानित करने तक का प्रयास करता है। लूटपाट, मकानों और दुकानों में आगजनी तथा दुर्बलों एवं असहायों को प्रताड़ित करना, स्त्रियों का अपमान तथा लोगों की नृषंस हत्याओं में सांप्रदायिक विदेश की भावना दिखायी पड़ती है। धर्म के माध्यम से राजनीति करने वाले व्यक्ति सांप्रदायिक व्यक्ति कहलाते हैं। धार्मिक उन्मादों को, भड़काकर, धर्म के अस्तित्व को खतरों में बताकर, धार्मिक मुक्ति के लिए उत्प्रेरित कर सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा दिया जाता है।

सांप्रदायिकता के आयाम

प्रसिद्ध विद्वान टी० के० उमन द्वारा सांप्रदायिकता के ६ आयामों की चर्चा की गयी है। इसमें आत्मसातकारी, कल्याणकारी, पलायनकारी, पृथक्तावादी तथा प्रतिकारात्मक सांप्रदायिकता सम्मिलित हैं। आत्मसातीकरण से संबद्ध सांप्रदायिकता का लक्ष्य किसी समुदाय विशेष का कल्याण करना होता है। जीवन स्तर में सुधार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी आधारभूत सुविधाओं का किसी खास संप्रदाय के लिए विस्तार करना इसका उद्देश्य होता है। पलायनवादी सांप्रदायिकता वह है, जिसमें एक छोटा धार्मिक समुदाय अपने को राजनीति से अलग रखता है जैसे बहाई समुदाय अपने सदस्यों को राजनीति में भाग लेने से रोकता है। प्रतिकारात्मक सांप्रदायिकता प्रतिषेध की भावना पर

आधारित होती है। इसके तहत किसी धार्मिक समुदाय द्वारा अन्य धार्मिक समुदायों के सदस्यों को क्षति पहुँचाना अपनी सांस्कृतिक विषिष्टता बनाये रखने का प्रयास करता है। उदाहरण के रूप में उत्तर-पूर्वी भारत में मिजो और नागाओं की मांग को देखा जा सकता है, अलगाववादी सांप्रदायिकता के अंतर्गत एक धार्मिक समुदाय राजनैतिक पहचान की मांग करता है और स्वतंत्र राज्य की चाह रखता है। आजाद कश्मीर व खालिस्तान की मांग इस प्रकृति की सांप्रदायिकता का उदाहरण है।

भारतीय समाज की प्रकृति और सांप्रदायिकता :

भारत का बहुलवादी समाज अनेक धार्मिक समूहों से मिलकर बना है, जो कई धार्मिक उपसमूहों में भी विभक्त है। हिन्दू धर्म पंथों में वर्गीकृत है जैसे आर्य समाज, वैव

समाज, सनातनी, वैश्व आदि जबकि इस्लाम धर्म एक ओर शिया और सुन्नियों में विभक्त है, तो दूसरी ओर अशरफ (कुलीन), असलम (जुलाहे, कसाई, बढई, तेली और अरजलों में)। भारत में सांप्रदायिकता के दुःप्रभावों का लंबा इतिहास रहा है। १८५७ में अंग्रेजों द्वारा हिन्दू मुस्लिम के बीच 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनायी गई। १९०६ में मार्ले-मिंटो अधिनियम में साम्प्रदायिकता के बीच प्रस्फुटित हुए और कालांतर में क्रिप्स प्रस्तावों में पाकिस्तान को अपरोक्ष समर्थन देकर सांप्रदायिकता की भावना को उद्देहित किया गया। निष्चित रूप से स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सांविधानिक दृष्टि से पंथ निरपेक्ष ढाँचे के बावजूद सांप्रदायिक मनोवृत्ति एवं तत्वों की उपस्थिति ने राष्ट्रिय सहिष्णुता को चोट पहुँचायी है।

धर्म एवं सांप्रदायिकता का भारतीय राजनीति के निर्धारक तत्वों के रूप में मुख्य स्थान रहा है। धर्म एवं राजनीति की अंतर्क्रिया ने सांप्रदायिकता को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। स्वतंत्र भारत में सांप्रदाय पंथ के आधार पर अनेक राजनीतिक दलों का गठन किया गया। चूँकी भारतीय समाज में धर्म जनमानस में रचा बसा है, इसलिए धार्मिक भावनाओं को उत्प्रेरित कर चुनावों में सांप्रदाय आधारित ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन देने का प्रयत्न किया गया। विष्व हिन्दू परिशद, बंजरग दल, शिवसेना, शिरोमणि अकाली दल, मुस्लिम लीग, राम राज्य परिशद् और हिन्दू महासभा द्वारा धार्मिक आचरणों को राजनीतिक षक्ति संबर्द्धन का माध्यम बनाया गया। इस संदर्भ में भारतीय राजव्यवस्था के विश्लेशक मारिस जोन्स का मानना हे कि, " सांप्रदाय के आधार पर गठित राजनीतिक दल संकीर्ण राजनीति में संकीर्ण हितों को प्रश्रय देते है। भारत में यह देखा गया है कि वोटबैंक की राजनीति के द्वारा धार्मिक अथवा सांप्रदायिक आधारों पर मतदान व्यवहार की प्रक्रिया को प्रभावित किया जाता है। १५वीं लोकसभा चुनाव के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों विशेषकर उत्तर प्रदेश में यह स्थिति विवाद का विशय बनी। भारत में विभिन्न धार्मिक दबाव गुटों द्वारा अपरे हित में राजनीतिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए शासन की नीतियों को प्रभावित

किया जाता है। उनके द्वारा प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से पंथ के आधार पर पृथक राज्य की मांग की जाती है।

सांप्रदायिकता के कारक :

भारत जैसे बहुलतावादी राष्ट्र में सांप्रदायवाद के विकास के पीछे एकाधिक कारक विद्यमान रहे हैं। ऐतिहासिक कारणों में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यिक प्राथमिकता द्वारा हिन्दू-मुस्लिम के बीच विद्वेष को फैलाना प्रमुख है। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विकास के बावजूद सामाजिक-आर्थिक असंतुलन एवं विशमताएं सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने के लिए जिम्मेदार रही है। नगरीकरण, तीव्र औद्योगिकीकरण ने जिन सामाजिक परिवर्तनों को उत्पन्न किया है, उससे सभी वर्ग अथवा समुदाय अपना सामंजस्य नहीं बिठा पाये है। अधिका, बेरोजगारी, आर्थिक पिछड़ेपन की स्थितियाँ और सामाजिक और आर्थिक असुरक्षाओं तथा चिंताओं ने विभिन्न सांप्रदायों को विचलित व्यवहार करने के लिए विवश किया है। इन सभी दुर्भाग्यपूर्ण स्थितियों के बीच विविध राजनीतिक दलों ने किसी भी माध्यम से सत्ता प्राप्ति हेतु जातिगत, सांप्रदायिकता को प्रतिस्पर्द्धी चुनावी राजनीति का उत्पाद माना है। भारत में विभिन्न धार्मिक समूहों अथवा समुदायों का सामाजिक-आर्थिक बहिष्करण और उनका राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से न जुड़ पाने की स्थितियाँ अविश्वास व असुरक्षा के भाव उत्पन्न कर सांप्रदायिक दंगों के लिए उत्प्रेरित करती है।

भारत में सांप्रदायिकता उन्माद के प्रमाण :

१९४६-४८ के दौरान सांप्रदायिक उन्माद, १९६४ में पूर्वी भारत के अनेक भागों- कलकत्ता, जमशेदपुर, राउरकेला एवं राँची में हुए सांप्रदायिक दंगे, १९६८ से १९७१ के बीच देश के विविध भागों में सांप्रदायिक हिंसा उपरोक्त अविश्वास और असुरक्षा की भावनाओं का ही परिणाम हैं। वर्ष १९७६ में तमिलनाडु के मीनाक्षी पुरम में दलितों का धर्म-परिवर्तन कराकर उन्हें मुस्लिम बनाये जाने से गंभीर विवाद उत्पन्न हो गया। इस समय विष्व हिन्दू परिशद् की हिन्दू हितों के रक्षक के रूप में भूमिका को सांप्रदायिक आधार पर देखा गया। इसी प्रकार वर्ष

१९८४में भारतीय प्रधानमंत्री की नृषंस हत्या के बाद दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगों में लगभग ३००० सिखों के मारे जाने सांप्रदायिक तत्वों की पहचान को उजागर करने वाला एक अन्य मामला १९८५ का षाहबानों प्रकरण था जिसमें सरकार द्वारा मुस्लिम कट्टरपंथियों के दबाव में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को बदलने की कार्यवाही की गयी। इसे अल्पसंख्यकों के तुष्टीकरण के तौर पर देखा गया। वर्ष १९९२ में बाबरी मस्जिद के विध्वंस के साथ रामजन्म भूमि आंदोलन ने भारत में सांप्रदायिक दंगों के विध्वंसक दुश्चक्र को पुरु किया। वर्ष १९९८ में गुजरात में बाध्यतापूर्वक धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर गिरिजाधरों पर हमले के बाद इसाई धर्मप्रचारकों की नृषंस हत्या (स्टेन्स हत्याकांड) से अल्पसंख्यकों के असुरक्षा का मामला सामने आया और धार्मिक स्वतंत्रता जैसे मूल अधिकार का अतिक्रमण हुआ। इसी क्रम में गुजरात में हुए गोधरा कांड के तांडव ने सांप्रदायिक उन्माद को जीवन-मरण का प्रण बना दिया। सन् २००८ में उड़ीसा के कंधमाल में हुए इसी प्रकृति दंगों में अनेक आदिवासी परिवार के घरों को जला दिया गया। वस्तुतः ऐसी स्थितियाँ एक असभ्य, बर्बर, अलोकतांत्रिक, अमानवीय मनोवृत्ति की ही सूचक है।

सांप्रदायिकता का दुश्प्रभाव :

सांप्रदायिकता की मानसिकता किसी खास धर्म समूह के निहित स्वार्थों की पूर्ति की दृष्टि से तो लाभदायक हो सकता है, लेकिन राष्ट्र की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाये रखने में बाधक है। यह राष्ट्रीय संस्कृति के बजाय स्वयं की उप संस्कृति विकसित करने हेतु बढ़ावा देता है। देश में शांति, सुरक्षा, समृद्धि, सद्भाव, सहिष्णुता की संस्कृति पर सांप्रदायिकता घातक प्रहार करती है, और राष्ट्र के कानून और व्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ उत्पन्न करती है। इसका कारण घृणा, द्वेष और प्रतिषेध की भावना पर आधारित होना है। इससे निर्दोश नागरिकों का अमूल्य जीवन नष्ट होता है, सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुँचती है, यातायात में अवरोध उत्पन्न होता है और शहर बंदी के दौरान दैनिक जीवन की आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति ठप्प हो जाती है। यह

विचारणीय तथ्य है कि शहरों में हुए सांप्रदायिक दंगों के बाद लगायी गयी बंदी में मरीज चिकित्सक तक न पहुँच पाने के चलते अपनी जान से हाथ धो बैठा है। इसी प्रकार आर्थिक गतिविधियों के केन्द्र वाले नगरों जैसे अहमदाबाद, मुंबई, मेरठ, अलीगढ़, नासिक, बड़ोदरा, दिल्ली में होनेवाले सांप्रदायिक दंगों से व्यापार-वाणिज्य बुरी तरह प्रभावित हो जाता है, और अंततः राष्ट्र की प्रगति एवं समृद्धि को भी चोट पहुँचती है।

सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयास :

इसलिए, सांप्रदायिकता को दूर करने के प्रयास करने ही होंगे। मूल्य आधारित राजनीति ओर मूल्य आधारित शिक्षा इस समस्या के समाधान में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। उल्लेखनीय है कि सन् २००८ में राष्ट्रीय एकता परिशद् की बैठक में सांप्रदायिक राजनीति करने वाले विभिन्न राजनीतिक दलों व संगठनों की मान्यता को समाप्त करने की अनुषंसा की गयी है। परिशद् की बैठक में विश्व हिन्दू परिशद्, बजरंग दल तथा शिव सेना की कार्यवाहियों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त की गयी। कम से कम राजनीतिक दलों हेतु ऐसी आचार संहिता का निर्माण होना जरूरी है, जिससे धर्म, भाशा, संप्रदाय जैसे गैर राजनीतिक तत्वों का चुनावी राजनीति में प्रयोग न हो। सर्वधर्म समभाव की स्थापना के लिए विभिन्न संप्रदायों की सहमति के साथ धार्मिक समन्वय समितियों की स्थापना इस दिशा में कारगर रणनीति हो सकती है। सांप्रदायिक दंगों से निपटने के लिए बनाये गये 'त्वरित कार्यवाही बल' का विस्तार एवं सशक्तीकरण किया जाना चाहिए। बहुसंख्यकों और अल्पसंख्यकों के हितों के मध्य संतुलन स्थापित कर अल्पसंख्यकों की वैध मांगों की सुनवाई व आवश्यकतानुसार स्वीकृती मिलनी चाहिए। आर्थिक विकास को संतुलित कर विकास जनित सामाजिक-आर्थिक विशमताओं को रोका जाना चाहिए और विकास के लाभों में सभी समुदायों की उचित भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और शिक्षा प्रणाली में आध्यात्मिक मूल्यों के समावेश की रणनीति राष्ट्रीय ज्ञान आयोग को बनानी चाहिए। वर्ष २००५ में सांप्रदायिक हिंसा से निपटने के लिए सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण विधेयक को राज्य सभा में

प्रस्तुत किया गया था। इसमें कानून व्यवस्था की स्थिति तथा सांप्रदायिक तनाव की स्पष्ट व्याख्या, सांप्रदायिक हिंसा के दोशियों को सामूहिक समुदाय के रूप में दंडित किये जाने का सुझाव और सांप्रदायिक हिंसा के मुकदमों की जांच-पड़ताल के लिए राज्यों में विशेष अदातल गठित करने का सुझाव है। आवश्यकता इस बात की है कि इस त्वरित गति से कानून बने।

निष्कर्ष:

भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ० ए० पी० जे० अब्दुल कलाम के शब्दों में कहा जा सकता है कि “भारत के लोगों के मनमस्तिष्क में एकात्मकता उत्पन्न करने हेतु भारतीयों में नैतिकता, सदाचार और आध्यात्मिकता की नींव डालनी होगी। आर्थिक समृद्धि के बीच सशक्त पुलों का निर्माण करना होगा। धर्म और विज्ञान के बीच समरूपता की स्थापना होने पर ही भारत में समृद्धि और शांति की स्थापना हो पायेगी। इसके लिए ‘मै और तू

का अहम ओर क्षुद्रता का त्याग आवश्यक है।” ७ दिसम्बर २००३ को नई दिल्ली में आयोजित ‘समरसता की संस्कृति तथा शांति की दिशा में अंतराष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में राष्ट्रपति कलाम द्वारा यह उद्बोधन निश्चित रूप से भारत की वैश्विक स्तर पर सांस्कृतिक साख अथवा पंथनिरपेक्ष छवि के निर्माण की नींव डाल सकता है। इस वाक्यांशों का अनुसरण अर्थों में भारत में सांप्रदायिकता की राजनीति का उपषमन करेगा।

संदर्भ ग्रन्थसूची :-

- एम० लक्ष्मीकान्त, भारत की राजव्यवस्था, टाटा मैग्राहिल प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली।
- दैनिक जागरण पत्रिका।
- प्रतियोगिता दर्पण।